राष्ट्रीय कृत बैंकों में धोखा-धड़ी के मामले

3454. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991–92 और 1992–93 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखाधड़ी, गबन, लूटपाट और जमाकर्ताओं के खातों की राशियों के दुर्विनियोजन के कितने मामले हुए और राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रत्येक वर्ष इनके कारण कुल कितना घाटा उठाना पड़ा;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन मामलों में कितने बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ; और

(ग) मध्य प्रदेश और उड़ीसा के किन-किन स्थानों के किन-किन बैंकों में ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अब्दार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान सूचना प्रणाली से पूछे गए तरीके की सूचना उपलब्ध नहीं होती है । तथापि, भारत में सरकारी क्षेत्र की बैंकों द्वारा वर्ष 1991 तथा 1992 के दौरान (सितम्बर, 1992 तक) भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई कुल धोखाधड़ियों की संख्या तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त धनराशि निम्नानुसार है :—

	धोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त धनराशि (करोड़ रुपये)
1991	1535	62.65
1992 (सितम्बर तक)	1247	99.22

Cases against DCM Ltd.

3455. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the Industrial Houses are indulging in wilful evasion of various Government taxes, thereby affecting adversely the revenue collections;

(b) if so, what are the total number of cases under Income Tax, Customs and Excise laws pending adjudication or otherwise against DCM Ltd.;

(c) what is the break-up of amounts involved case-wise;

(d) what are the details of the cases confirmed by the adjudicating authorities, case-wise; and

(e) what action Government are taking to realise the dispute amounts where Courts have granted stay orders ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASEKHAR MURTHY) : (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Dues against M/s. GRASIM Industries Ltd.

3456. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the industrial houses are indulging in wilful evasion of various Government taxes, thereby affecting adversely the revenue collections;

(b) if so, what is the total number of cases under Income Tax, Customs and Excise laws pending adjudication or otherwise against GRASIM Industries Ltd.;

(c) what is the break-up of amounts involved case-wise;

(d) what are the details of the cues confirmed by the adjudicating authorities, case-wise; and